

मुकदमों का विवरण

अभिषेक शर्मा बनाम।

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2011 की आपराधिक अपील संख्या 1473) 18 अक्टूबर, 2023

[अभय एस. ओका और संजय करोल, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:पीड़ित-मृतक ने चार मृत्यु घोषणाएँ दीं।उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया।302 आई. पी. सी. जैसा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया है।

दंड संहिता, **1860** -धारा. **302**-साक्ष्य अधिनियम, **1872**-कई मृत्यु घोषणाएँ-अभियोजन मामला कि अपीलार्थी और पीड़ित के बीच झगड़ा हुआ था, क्योंकि पीड़ित का अपने मालिक के लिए संबंध था न कि अपीलार्थी के लिए-अपीलार्थी पीड़ित को एक स्कूल के पास एक खुली जगह पर ले गया और एक बहस के बीच उसे फिर से स्थापित कर दिया-पीड़ित की मृत्यु हो गई-पीड़ित ने चार मृत्यु घोषणाएँ दी थीं-निचली अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए अपीलार्थी-स्वामित्व:

आयोजित किया गया:डीडी-आई से पता चलता है कि यह तीसरे व्यक्ति में दर्ज किया गया था, क्योंकि पीडब्लू-16-एसआई ने घटना की सूचना दी थी-अदालत के समक्ष बयान यह है कि संचालक 'डीओ रूम' में आया और बताया कि पीडब्लू-16 ने एक लड़की को जलते हुए पाया था, और यह उसके लिए है कि उसने कहा कि अपीलकर्ता ने उसके साथ ऐसा किया था-यदि मृतक का बयान, जैसा कि पीडब्लू-16 को बताया गया था, अदालत के समक्ष था, तो इसे एस के अर्थ के भीतर एक मृत्यु घोषणा माना जा सकता था।32 आई. ई. ए.-डी. डी.-II, वास्तव में, पी. डब्ल्यू.-8-डॉक्टर द्वारा किए गए मेडिको-लीगल इन्क्वायरी रजिस्टर में एक प्रविष्टि है-यह सच है कि मृत्यु की घोषणा को संक्षिप्तता के कारण खारिज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इसमें मृतक की स्थिति का निकटतम कारण और उसका कारण होना चाहिए-यहाँ, यह जलने की चोटों की उपस्थिति बताता है और कहता है कि वही अपीलार्थी के कारण हुआ था, जो, यकीनन, असंवेदनशील है-दोषी-अपीलार्थी की कोई विशेष पहचान नहीं है, और न ही उस साधन का उल्लेख है जिसके माध्यम से चोटों को इंफ्लेक्टेड (पेट्रोल) किया गया था-डी. डी.-III 891

890

अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.)

पीडब्लू-17-एस. आई. को दिया गया था-यह तीसरा बयान दिए जाने के बावजूद, डॉक्टर या मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, जो विवेक के नियम के रूप में

अभियोजन पक्ष को समर्थन देता है-यह रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिस समय तीसरा बयान दर्ज किया गया था, उस समय मृतक को उसकी चोटों के लिए इलाज किया गया था-हालाँकि, यह उपचार की प्रकृति और उसे किस तरह की दवाएं दी गई थीं, इसके बारे में सामने नहीं आया है-उसके इलाज के लिए जिम्मेदार चिकित्सा दल द्वारा सकारात्मक बयान के अभाव में, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि दी गई दवाओं से मृतक की मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का कोई प्रभाव नहीं था-इसलिए, डीडी-III-डीडी-को लेकर संदेह है।[पैरा 15,16,17,19,26]

मृत्यु घोषणा-कई मृत्यु घोषणाएँ-कई मृत्यु घोषणाओं से जुड़े मामले पर विचार करते समय न्यायालय निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करेगा:

आयोजित किया गया:1. सभी मृत्यु घोषणाओं के लिए प्राथमिक आवश्यकता यह है कि वे स्वैच्छिक और विश्वसनीय होने चाहिए और इस तरह के बयान मन की एक निश्चित स्थिति में होने चाहिए।2. सभी अंतिम घोषणाएं सुसंगत होनी चाहिए-दूसरे शब्दों में, इस तरह के बयानों के बीच विसंगतियां इसकी विश्वसनीयता को हिलाने के लिए 'भौतिक' होनी चाहिए;3. जब विभिन्न मृत्यु घोषणाओं के बीच विसंगतियां पाई जाती हैं, तो मृत्यु घोषणाओं की सामग्री की पुष्टि के उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है।4. मृत्यु घोषणा के रूप में माने जाने वाले बयान की व्याख्या आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में की जानी चाहिए।5. प्रत्येक घोषणा की अपने गुण-दोष के आधार पर जांच की जानी चाहिए-न्यायालय को यह जांच करनी होगी कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए किन बयानों पर भरोसा किया जा सकता है।6. जब वहाँ

892

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

यदि विसंगतियाँ हैं, तो मजिस्ट्रेट या उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान पर सच्चाई और संदेह से मुक्त होने के अनिवार्य गुणों के अधीन भरोसा किया जा सकता है।7. विसंगतियों की उपस्थिति में, इस तरह की घोषणा करने वाले व्यक्ति की चिकित्सा क्षमता, प्रासंगिक समय पर, अन्य कारकों जैसे रिश्तेदारों द्वारा शिक्षण की संभावना आदि के साथ महत्वपूर्ण हो जाती है। [पैरा 9]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

कमला बनाम पंजाब राज्य (1993) 1 एस. सी. सी. 1; पंजाब राज्य बनाम परवीन

कुमार (2005) 9 एससीसी 769:[2005] 9 एससीसी 769; अमोल सिंह बनाम एमपी राज्य (2008) 5 एससीसी 468:[2008] 8 एस. सी. आर. 956; लखन बनाम एम. पी. राज्य (2010) 8

एससीसी 514:[2010] 9 एस. सी. आर. 705; माखन सिंह बनाम हरियाणा राज्य

(2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1019; आशाबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013)

2 एस. सी. सी. 224:[2013] 1 एस. सी. आर. 115; जगबीर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2019) 8

एससीसी 779:[2019] 11 एस. सी. आर. 1137; उत्तम बनाम महाराष्ट्र राज्य (2022) 8 एस. सी. सी. 576-पर निर्भर था।

शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2008) 4 एससीसी 265:[2008] 2 एससीआर 959;

चाको बनाम केरल राज्य (2003) 1 एससीसी 112; पी. वी. राधाकृष्ण बनाम राज्य

कर्नाटक (2003) 6 एससीसी 443:[2003] 1 पूरक।एस. सी. आर. 745; सुरिंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2011) 10 एस. सी. सी. 173:[2011] 12 एस. सी. आर. 1205; खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 22:[1958] एस. सी. आर. 552; हरि ओबुला रेड्डी

और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1981) 3 एससीसी 675; पुलिचेरला नागराजू उर्फ नागराजा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) 11 एससीसी

444:[2006] 4 पूरक।एस. सी. आर. 633-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2011 की आपराधिक अपील No.1473

2009 के सी. आर. एल. ए. No.431 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 31.05.2010 के निर्णय और आदेश से

रूप:

सुश्री कामिनी जैसवाल, अनीश ढींगरा, सुश्री रानी मिश्रा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

893

अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.)

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., सुश्री किरण सूरी, सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री स्निधा मेहरा, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, संजय कुमार। त्यागी, अदित खुराना, शुभ्रांशु पाधी, उदय खन्ना, अरुण कुमार यादव, श्रीकांत नीलप्पा तेरदल, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

संजय करोल जे।

1. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2009 की आपराधिक अपील संख्या 431 दिनांक 31 मई 2010 में पारित एक निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश पर आक्षेप करती है, जिसमें अपीलार्थी अभिषेक शर्मा को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा

सुनाई गई है, जैसा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा 30 अप्रैल 2009 के फैसले के माध्यम से दिया गया था।

तथ्य

2. निम्नलिखित न्यायालयों के निर्णयों में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, वे इस प्रकार हैं:-

2.1 अभिषेक शर्मा 2 और मनदीप कौर 3 सरस्वती विहार, दिल्ली में मेसर्स साईं टेलीकॉम में सहकर्मी थे, जहाँ पूर्व ग्राहक सेवा कार्यकारी थे और बाद वाला टीम लीडर/संचालन प्रबंधक था। 20-21 सितंबर 2007 की दरम्यानी रात को, मृतक क्वीन मैरी स्कूल, मॉडल टाउन, दिल्ली के पास मिट्टी में डूबा हुआ पाया गया। एल. एन. जे. पी. अस्पताल और महाराजा अग्रसेन अस्पताल नामक दो अलग-अलग अस्पतालों में उन्हें बचाने के प्रयासों के बावजूद, 3 अक्टूबर 2007 को उनका निधन हो गया।

2.2 यह दर्ज किया गया है कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच एक दोस्ती विकसित हुई थी, और दोषी-अपीलकर्ता अक्सर काम के बाद उसे घर ले जाता था, जो लगभग आधी रात को समाप्त हो जाता था। कथित तौर पर, उसके संबंध उसके लिए नहीं बल्कि उनके मालिक के लिए होने के संबंध में एक झगड़े के कारण, वह उसे एक स्कूल के पास एक खुली जगह पर ले गया और एक बहस के बीच, उसे फिर से स्थापित कर दिया।

1 संक्षेप में आई. पी. सी.

2 इसके बाद "दोषी-अपीलार्थी" के रूप में संदर्भित 3 इसके बाद "मृत" के रूप में संदर्भित

894

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

2.3 अस्पताल जाते समय मृतक ने अनूप सिंह (पीडब्लू-16) को बताया कि दोषी-अपीलार्थी ने उसे आग लगा दी थी। एस. आई. बलवंत सिंह (पीडब्लू-17) ने सिपाही अमरजीत सिंह के साथ उसका बयान दर्ज किया, जिसके आधार पर आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। दोषी-अपीलार्थी को 21 सितंबर 2007 को गिरफ्तार किया गया था। जाँच पूरी होने पर, 6 फरवरी 2008 को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए ट्रायल कोर्ट में चालान पेश किया गया था।

परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष

3. अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने कुल 25 गवाहों से पूछताछ की। निम्नलिखित उसका एक सारणीबद्ध प्रतिनिधित्व है:

श्री. नहीं।	औपचारिक	भौतिक गवाह	चिकित्सकीय
-------------	---------	------------	------------

	गवाह		गवाह
1	पीडब्लू1-एच. सी. राजीव कुमार एक कर्तव्य अधिकारी	पीडब्लू 16-एसआई अनूप सिंह प्रभारी पीसीआर वैन कमांडर 63	पीडब्लू 7-डॉ. लता सीनियर रेजिडेंट ने मृतक की मृत्यु का सारांश तैयार किया
2	पीडब्लू2-सी. टी. दलबीर सिंह फोटोग्राफर	पीडब्लू15-सी. टी. सुबोध कुमार पी. सी. आर. वैन में पीडब्लू16 के साथ हैं।	पीडब्लू8-डॉ. एस. एन. बसना एल. एन. जे. पी. अस्पताल में सी. एम. ओ. के रूप में कार्यरत हैं।
3	पीडब्लू4-एस. आई. मनोहर ला ड्राफ्ट्समैन	पीडब्लू 17-एस. आई. बलवंत सिंह ने घायलों का एम. एल. सी. प्राप्त किया	पीडब्लू12-डॉ. के. गोयल ने मृतक का पोस्टमॉर्टम किया
4	पीडब्लू9-सी. टी. मुकेश सी. एफ. एस. आई. में जमा करने के लिए सीलबंद पार्सल ले गए।	पीडब्लू 13-सी. टी. परमजीत सिंह ने एस. आई. बलवंत सिंह के साथ जांच की।	पीडब्लू18-डॉ. राज ने मृतक की जांच की

- 895

अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र [संजय करोल, जे.] 896

5	पीडब्लू10-एच. सी. प्रमोद कुमार एम. एच. सी. (एम) में तैनात	पीडब्लू5-श्रीमती. मृतक की मां जैस्मर कौर	पीडब्लू19-डॉ. संजय एस. आर. सर्जरी ने आरोपी अभिषेक शर्मा की जांच की।
6	पीडब्लू11-एचसी नरेश कुमार एस. आई. बलवंत सिंह के साथ महाराजा अगरसेन अस्पताल गए।	पीडब्लू6-एस. मेसर्स साई टेलीकॉम के भागीदार याशिन नागपाल, जहाँ मृतक और आरोपी काम कर रहे थे	पीडब्लू20-डॉ. गीता रामकृष्ण सूक्ष्म जीवविज्ञानी जिन्होंने मृतक के रक्त के नमूने की जांच की
7	पीडब्लू 14-एसआई सुरेश	पीडब्लू 3-मृतक के बहनोई हेमंत	पीडब्लू 22-डॉ. आशीष शर्मा ने

	चंद निरीक्षण के लिए मौके पर गए।	अनेजा	एमएलसी साबित किया
8	पीडब्लू21-एस. महाराजा अगरसेन अस्पताल के रिकॉर्ड क्लर्क के. के. शर्मा		पीडब्लू 24-श्री प्रदीप कुमार मिश्रा जूनियर साइंटिफिक सी. ऑफिसर, सी. एफ. एस. एल., कलकत्ता ने रक्त और बालों के नमूनों की जांच की।
9	पीडब्लू 23-इंस्पेक्टर हरीश चंदर ने एस. आई. द्वारा स्थल योजना तैयार कराई; एम. एच. सी. (एम) का बयान दर्ज किया;		पीडब्लू 25-श्री विजयंत्र मुखोपाध्याय जूनियर साइंटिफिक सी. ऑफिसर, सी. एफ. एस. एल., कलकत्ता ने जली हुई सामग्री के साथ प्लास्टिक की बोतल की जांच की।

4. पीडब्लू18, पीडब्लू8 और पीडब्लू12 (डॉक्टरों) की गवाही ने स्थापित किया है कि मृतक की मृत्यु जलने की चोटों, पूर्व-शव परीक्षण के कारण हुई थी, जिसकी पुष्टि पीडब्लू16, पीडब्लू17, पीडब्लू5 और पीडब्लू6 द्वारा की गई है।

4.1 मृतक ने चार मृत्यु घोषणाएँ दीं। पहला 4 एक पुलिस अधिकारी को पी. डब्ल्यू. 16 यानी उस व्यक्ति को दिया गया था, जो

4 आसानी के लिए, डीडी-आई

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

पी. सी. आर. वैन अपराध स्थल पर पहुंची और मृतक को एल. एन. जे. पी. अस्पताल ले गई। भले ही जमीन पर बचाव पक्ष ने इस घोषणा की सत्यता पर सवाल उठाया कि पीडब्लू15, जो पीडब्लू16 के साथ था, जब मृतक को अस्पताल ले जाया गया था, ने बयान नहीं सुना था, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि यह स्थापित किया गया था क्योंकि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि उसे इस तरह से बताने के लिए सिखाया गया था या उसके इस तरह का बयान देने की कोई संभावना नहीं थी।

4.2 दूसरा 5 डॉ. राज (पीडब्लू-18) को दिया गया, जिन्होंने मृतक की जांच की थी और एमएलसी तैयार किया था। उसने अपदस्थ कर दिया कि मृतक को बयान देना था और "अभिषेक द्वारा" बाद

में नहीं लिखा गया था। पीडब्लू 8 ने उनके बयान की पुष्टि की। डॉक्टरों की गवाही को चुनौती नहीं दी गई, और इसलिए, गवाही को अविश्वसनीय कहने के बचाव पक्ष के प्रयासों को ट्रायल कोर्ट द्वारा सही नहीं पाया गया।

4.3 तीसरी 6 मृत्यु घोषणा पीडब्लू 17 को दी गई थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बचाव पक्ष ने इस घोषणा पर इस आधार पर सवाल उठाया कि पुलिस ने एक खाली कागज पर मृतक के हस्ताक्षर प्राप्त किए थे, और उसी को एक प्राथमिकी में हेरफेर किया गया था। बचाव पक्ष का यह तर्क कि एक डॉक्टर ने इसे प्रमाणित नहीं किया, अदालत के पक्ष में नहीं था।

जिसमें कहा गया है कि "शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य" 7 के अनुसार,

डॉक्टर का अनुमोदन केवल विवेक की बात है। अदालत ने माना कि मृतक ने स्पष्ट रूप से दोषी-अपीलार्थी का उसे मारने का मकसद और इरादा दिखाया था।

4.4 चौथा 8 मृत्यु घोषणा पत्र पीडब्लू 5 (मृतक की माँ) को दिया गया था। उसके बयान, मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में, यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि मृतक बयान देने के लिए मानसिक स्थिति में था। यह बात सामने आई है कि यह बयान 22 सितंबर 2007 को दिया गया था।

5 आसानी के लिए, डीडी-II 6 आसानी के लिए, डीडी-III 7 (2008) 4 एससीसी 265 8 आसानी के लिए, डीडी-IV 897

अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [संजय करोल, जे.] 898

उनकी हालत बिगड़ने से बहुत पहले, जिसके कारण उन्हें 3 अक्टूबर 2007 को उनकी मृत्यु से छह दिन पहले वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था।

4.5 उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, ट्रायल कोर्ट ने सभी चार मृत्यु घोषणाओं को सुसंगत, स्वेच्छा से की गई और एक निश्चित मानसिक स्थिति में पाया। इसके अलावा, पीडब्लू 6, अर्थात् यासीन नागपाल की गवाही के संबंध में, यह स्थापित किया गया है कि मृतक को आखिरी बार दोषी-अपीलार्थी की कंपनी में देखा गया था जब वे लगभग 12 बजे कार्यालय से निकले थे: 30 एएम। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत दोषी-अपीलार्थी के बयान में कहा गया है कि उसने 12 साल की उम्र में कार्यालय छोड़ दिया: 00 एएम और मृतक अभी भी कार्यालय में थे।

4.6 अदालत ने पाया कि दोषी-अपीलार्थी का बयान विश्वसनीय नहीं था, और पीडब्लू 6 का बयान बेदाग और बिना चुनौती वाला था।

4.7 इसे ध्यान में रखते हुए, दोषी-अपीलार्थी को दोषी पाया गया और आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत दोषी ठहराया गया।

उच्च न्यायालय के परिणाम

5. यह देखा गया कि मृत्यु की नरघातक प्रकृति निर्विवाद है। प्रत्येक अंतिम घोषणा के संबंध में, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा लिए गए निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और कहा कि अपील

गुण-दोष से रहित थी।ऐसी प्रत्येक घोषणा के अनुसार उच्च न्यायालय के तर्क का उल्लेख नीचे किया गया है:-

5.1 पीडब्लू16 को दिए गए डीडी-I को इस आधार पर चुनौती देने की मांग की गई थी कि पीडब्लू15 ने बयान दिए जाने को नहीं सुना था।अदालत ने नोट किया कि अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू15 ने कहा था कि मृतक ने "इस तथ्य को बताया होगा कि दोषी-अपीलकर्ता घटना के लिए जिम्मेदार था"।यह भी देखा गया कि इस तरह के वाहन का चालक, जब गंभीर रूप से घायल रोगी को सायरन बजाते हुए अस्पताल ले जाने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने वह नहीं सुना जो मृतक ने पीडब्लू 16 को बताया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

5.2 डी. डी.-II को पी. डब्ल्यू. 18 के लिए बनाया गया था, जो, यह देखा गया है, पूरी तरह से पी. डब्ल्यू. 16 के लिए बनाए गए डी. डी.-I के अनुरूप था।संबंधित चिकित्सक ने इस तरह का बयान देते समय मृतक की शारीरिक स्थिति के बारे में भी बयान दिया है।"अभिषेक द्वारा" को जोड़ने को उच्च न्यायालय द्वारा विश्वसनीय नहीं पाया गया क्योंकि पीडब्लू 18 ने इससे इनकार किया है, और डॉक्टरों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया गया है।

5.3 डीडी-III को सुबह 3:30 बजे से पीडब्लू 17 तक बनाया गया था।इस बयान में दोषी-अपीलार्थी का भी नाम है।यह देखा गया कि सुबह 1.4 से 3:30 बजे के बीच, मृतक द्वारा लगातार तीन बयान दिए गए, और जब से वह जली हुई स्थिति में पाई गई, तब से लेकर प्राथमिकी दर्ज करने तक का समय मुश्किल से दो घंटे का है।

5.4 डीडी-IV को इस आधार पर बदनाम करने की मांग की गई थी कि पीडब्लू5 एक इच्छुक गवाह था।इस तर्क को "शायद ही कोई तर्क" कहा गया है, और इसलिए, उच्च न्यायालय को देखते हुए, डीडी-IV भी साबित हुआ।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष एक अतिरिक्त आधार यह था कि 25 प्रतिशत जलने वाले व्यक्ति विस्तृत बयान नहीं दे सकते थे।अदालत द्वारा इसकी अवहेलना की गई, यह देखते हुए कि एक डॉक्टर ने उसकी मानसिक स्थिति के लिए विशेष रूप से गवाही दी थी।इसके अतिरिक्त, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय नियमों के अध्याय 13 के संबंध में प्रस्तुत करना, जो मृत्यु घोषणाओं को दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, दोषी-अपीलार्थी के लिए कोई सहायक नहीं माना गया क्योंकि यह देखा गया कि केवल नियमों का पालन नहीं किया गया था, मृत्यु घोषणाओं को खारिज नहीं किया जा सकता था यदि वे सभी सावधानियों को लागू करने के बाद सख्त जांच का सामना करते थे।

7. उपरोक्त कारणों से, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी, पश्चिम दिल्ली के फैसले को लागू किया गया था।

हमारा दृष्टिकोण

8. इस मामले के गुण-दोष पर आगे बढ़ने से पहले, कई मृत्यु घोषणाओं से जुड़े मामलों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विभिन्न सिद्धांतों की सराहना करना उचित होगा।

899

अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [संजय करोल, जे.] 900 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

8.1 कमला बनाम पंजाब राज्य **9** के मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया है:

“5. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि मृत्यु घोषणा दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकती है बशर्ते कि यह असंवेदनशीलता से मुक्त हो और विभिन्न परीक्षणों को संतुष्ट करे (खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य [ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 22:1958 एससीआर 552:1958 क्रि एलजे 106])। इस मामले में निर्धारित अनुपात को बाद के कई मामलों में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है। उन सभी मामलों में यह भी तय किया जाता है कि बयान पूरे समय सुसंगत होना चाहिए यदि मृतक को इस तरह की मृत्यु घोषणा करने के कई अवसर मिले, अर्थात्, यदि एक से अधिक मृत्यु घोषणाएँ हैं, तो वे सुसंगत होनी चाहिए। यदि एक मृत्यु घोषणा स्वैच्छिक, विश्वसनीय और मानसिक स्थिति में की गई पाई जाती है, तो बिना किसी पुष्टि के उस पर भरोसा किया जा सकता है। एक ऐसे मामले में जहाँ एक से अधिक मृत्यु घोषणाएँ हैं, यदि एक और दूसरे के बीच कुछ विसंगतियाँ देखी जाती हैं, तो अदालत को विसंगतियों की प्रकृति की जांच करनी होगी, अर्थात् वे भौतिक हैं या नहीं। विभिन्न अंतिम घोषणाओं की सामग्री की जांच करने में, ऐसी स्थिति में, अदालत को आसपास के विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में इसकी जांच करनी होती है।”

8.2. पंजाब राज्य बनाम परवीन कुमार **10** के मामले में, यह अदालत आगे

यह देखा गया: “10. अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि मृत्यु घोषणा सत्य है। यदि दो अलग-अलग संस्करण देने वाली दो मृत्यु घोषणाएँ हैं, तो मृत्यु घोषणाओं की सच्चाई के बारे में एक गंभीर संदेह पैदा होता है। यह हो सकता है कि यदि अभिलेख पर कोई अन्य विश्वसनीय साक्ष्य था, तो यह न्यायालय मृत्यु घोषणाओं की सच्चाई का परीक्षण करने के लिए इस तरह के पुष्टिकारक साक्ष्य पर विचार कर सकता था।

9 (1993) 1 एससीसी 1 (2-न्यायाधीश पीठ) 10 (2005) 9 एससीसी 769 (2-न्यायाधीश पीठ)

8.3. अमोल सिंह बनाम एम. पी. राज्य **11** में,

“13. ... हालाँकि, यदि एक मृत्यु घोषणा और दूसरे के बीच कुछ विसंगतियाँ देखी जाती हैं, तो अदालत को विसंगतियों की प्रकृति की जांच करनी होगी, अर्थात्, क्या वे भौतिक हैं या नहीं। विभिन्न अंतिम घोषणाओं की सामग्री की जांच करते समय, ऐसी स्थिति में, अदालत को आसपास के विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में इसकी जांच करनी होती है।”

8.4. कई मृत्यु घोषणाओं का सामना करते हुए, लखन में यह अदालत

v. एम. पी. 12 की स्थिति देखी गई -

“21. ... यदि कई मृत्यु घोषणाएँ हैं और उनके बीच विसंगतियाँ हैं, तो आम तौर पर, मजिस्ट्रेट की तरह उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज की गई मृत्यु घोषणा पर भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते कि इसकी सच्चाई के बारे में किसी भी संदेह को जन्म देने वाली कोई परिस्थिति न हो। यदि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें घोषणा की गई थी, स्वेच्छा से नहीं और यहां तक कि अन्यथा भी, यह अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, तो अदालत को एक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों की बहुत सावधानी से जांच करनी होगी और निर्णय लेना होगा कि कौन सी घोषणाएं निर्भर करने योग्य हैं।”

इस फैसले को हाल ही में इस अदालत द्वारा भी संदर्भित किया गया था

माखन सिंह बनाम हरियाणा राज्य **13.**

8.5. आशाबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, 14 में न्यायालय ने कहा:-

“15. जब कई मृत्यु घोषणाएँ होती हैं, तो प्रत्येक मृत्यु घोषणा का अलग से मूल्यांकन और मूल्यांकन किया जाना चाहिए और स्वतंत्र रूप से इसके प्रमाणिक मूल्य के रूप में इसकी योग्यता पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और एक को दूसरे में कुछ भिन्नताओं के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।”

11 (2008) 5 एस. सी. सी. 468 (2-न्यायाधीश पीठ) 12 (2010) 8 एस. सी. सी. 514 (2-न्यायाधीश पीठ)

13 (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1019 (2-न्यायाधीश पीठ) 14 (2013) 2 एस. सी. सी. 224 (2-न्यायाधीश पीठ)

901

अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र [संजय करोल, जे.] 902 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

8.6. जगबीर सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), 15 में निम्नलिखित

सिद्धांतों का पालन किया गया: 31. निर्णयों के एक सर्वेक्षण से पता चलेगा कि घोषणाओं के सिद्धांतों को निम्नानुसार निकाला जा सकता है:

....

31.6. हालाँकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ एक से अधिक मृत्यु की घोषणा हो। यदि एक से अधिक मृत्यु घोषणाएँ हैं, तो मृत्यु घोषणाएँ पूरी तरह से एक दूसरे से सहमत हो सकती हैं। वहाँ मरने वाली घोषणाएँ हो सकती हैं जहाँ घोषणाओं के बीच विसंगतियाँ सामने आती हैं। इसके बाद अदालत को विसंगतियों की सीमा पर विचार करना होगा। विसंगतियाँ सुलह योग्य साबित हो सकती हैं।

31.7. ऐसे मामलों में, जहाँ विसंगतियाँ विस्तार या विवरण के किसी मामले में जाती हैं, लेकिन जहाँ तक अभियुक्त का संबंध है, तो न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री को

देखेगा कि किस मृत्यु घोषणा पर भरोसा किया जाना है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि वे अविश्वसनीय हैं।

31.8.मामलों की तीसरी श्रेणी यह है कि जहां एक से अधिक मृत्यु घोषणाएं हैं और घोषणाओं के बीच विसंगतियां पूर्ण हैं और मृत्यु घोषणाएं एक दूसरे के लिए अप्रिय होने के कारण अपरिवर्तनीय हैं।मृत्यु घोषणा में, अभियुक्त को बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और मृत्यु का कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के दरवाजे पर रखा जा सकता है।इसके बाद एक और मृत्यु घोषणा की जा सकती है जो अंतिम मृत्यु घोषणा के बिल्कुल विपरीत है।वास्तव में, उस परिदृश्य में, यह एक असंगत मृत्यु घोषणा का सवाल नहीं हो सकता है, बल्कि एक मृत्यु घोषणा हो सकती है जो पहले दी गई मृत्यु घोषणा के पूरी तरह से विपरीत है।दो से अधिक हो सकते हैं।”

15 (2019) 8 एस. सी. सी. 779 (2-न्यायाधीश पीठ)

8.7.उत्तम बनाम महाराष्ट्र राज्य, 16 में इस न्यायालय ने कहा:

“15. मृतक द्वारा की गई कई मृत्यु घोषणाओं से जुड़े मामलों में, विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि न्यायालय द्वारा उक्त मृत्यु घोषणाओं में से किस पर विश्वास किया जाना चाहिए और न्यायसंगत और वैध निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कौन से मार्गदर्शक कारक होंगे।समस्या और भी जटिल हो जाती है जब मृतक द्वारा की गई मृत्यु घोषणाएं विरोधाभासी पाई जाती हैं।ऐसी स्थिति का सामना करते हुए, अदालत से अपेक्षा की जाएगी कि वह सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य भौतिक सबूतों द्वारा किन अंतिम घोषणाओं की पुष्टि की जा सकती है।समान महत्व की बात यह है कि संबंधित समय पर मृतक की स्थिति, अभिलेख पर लाए गए चिकित्सा साक्ष्य जो मृतक की शारीरिक और मानसिक स्थिति, करीबी रिश्तेदारों/परिवार के सदस्यों द्वारा मृतक को उकसाने/पढ़ाने के दायरे और अन्य सभी परिचर परिस्थितियों का संकेत देते हैं जो अदालत को अपने विवेक का प्रयोग करने में मदद करेंगे।”

9. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं, जिन पर एक न्यायालय को कई मृत्यु घोषणाओं से जुड़े मामले पर विचार करते समय विचार करना चाहिए:

9.1 सभी मृत्यु घोषणाओं के लिए प्राथमिक आवश्यकता यह है कि वे स्वैच्छिक और विश्वसनीय होने चाहिए और इस तरह के बयान मन की एक निश्चित स्थिति में होने चाहिए।

9.2 सभी मृत्यु घोषणाएं सुसंगत होनी चाहिए।दूसरे शब्दों में, इस तरह के बयानों के बीच विसंगतियां इसकी विश्वसनीयता को हिलाने के लिए 'भौतिक' होनी चाहिए।

9.3 जब विभिन्न मृत्यु घोषणाओं के बीच विसंगतियां पाई जाती हैं, तो मृत्यु घोषणाओं की सामग्री की पुष्टि के उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है।

16 (2022) 8 एस. सी. सी. 576 (2-न्यायाधीश पीठ)

अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [संजय करोल, जे.] 904

9.4 मृत्यु घोषणा के रूप में माने जाने वाले बयान की व्याख्या आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में की जानी चाहिए।

9.5 प्रत्येक घोषणा की अपने गुण-दोष के आधार पर जांच की जानी चाहिए। अदालत को इस बात की जांच करनी होगी कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए किस बयान पर भरोसा किया जा सकता है।

9.6 जब विसंगतियां होती हैं, तो मजिस्ट्रेट या उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान पर सच्चाई और संदेह से मुक्त होने के अनिवार्य गुणों के अधीन भरोसा किया जा सकता है।

9.7 विसंगतियों की उपस्थिति में, इस तरह की घोषणा करने वाले व्यक्ति की चिकित्सा क्षमता, प्रासंगिक समय पर, अन्य कारकों जैसे रिश्तेदारों द्वारा शिक्षण की संभावना आदि के साथ महत्वपूर्ण हो जाती है।

10. हमें इस अदालत के कुछ फैसलों पर भी ध्यान देना चाहिए जहां मृतक को लगी जलने की चोटों की सीमा पर विचार किया गया था।

10.1 चाको बनाम केरल राज्य 17 के मामले में इस अदालत ने 70 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति द्वारा की गई मृत्यु घोषणा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जो 80 प्रतिशत जल गया था। इसमें, जलने के 8-9 घंटे बाद घोषणा दर्ज की गई थी, जिसमें उद्देश्य और तरीके के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया था। यह राय दी गई थी कि घाव के प्रमाण पत्र में "सचेत, बात करने" के रूप में वर्णित रोगी की स्थिति अपने आप में ऐसी घोषणा करने वाले रोगी की स्थिति की गवाही नहीं देगी, न ही डॉक्टर या जांच अधिकारी का मौखिक साक्ष्य होगा।

10.2 पी. वी. राधाकृष्ण बनाम कर्नाटक राज्य 18 में यह था

यह देखा गया कि कोई कठोर और तेज नियम नहीं हो सकता है, इस सवाल पर एक समान आवेदन के लिए खुद को उधार देना कि क्या जलने का प्रतिशत पर्याप्त है, मृत्यु घोषणा की विश्वसनीयता को प्रभावित करने के लिए एक निर्धारक कारक है। वैसा ही।

17 (2003) 1 एस. सी. सी. 112 (2-न्यायाधीश पीठ) 18 (2003) 6 एस. सी. सी. 443 (2-न्यायाधीश पीठ)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

यह जलन की प्रकृति, शरीर के अंगों के बाहर निकलने और मानसिक क्षमताओं के साथ-साथ अन्य कारकों पर निर्भर करेगा।

10.3 सुरिंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य 19 में मृत्यु

95-97% जलने की चोटों वाले व्यक्ति द्वारा की गई घोषणा को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि घोषणा करते समय, मृतक को फोर्टविन और पेथिडाइन इंजेक्शन की सूजन थी, जिसके कारण वह सामान्य सतर्कता नहीं रख सकती थी।

11. उत्तम (ऊपर) में इस न्यायालय ने खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य 20 में दिए गए सिद्धांत का पालन किया कि मृत्यु घोषणा की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए, अदालत को परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा जैसे कि मरने वाले व्यक्ति को अवलोकन के लिए अवसर, उदाहरण के लिए, क्या पर्याप्त प्रकाश था यदि अपराध रात में किया गया था; क्या व्यक्ति की इस तथ्य को याद रखने की क्षमता, जब वह बयान दे रहा था, अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से बाधित नहीं हुई थी; कि बयान पूरे समय सुसंगत रहा है यदि उसके पास आधिकारिक रिकॉर्ड के अलावा मृत्यु घोषणा करने के कई अवसर थे; और यह कि बयान जल्द से जल्द अवसर पर दिया गया था और इच्छुक पक्षों द्वारा शिक्षण का परिणाम नहीं था।

12. उपरोक्त निकाले गए सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद, अब हम तत्काल तथ्यों में उनकी जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

13. डी. डी.-आई. निम्नानुसार है: “डी. डी. सं. 8 ए डी. टी. 21/09/07 पी. एस. मॉडल टाउन दिल्ली पी. सी. आर. और प्रेषण से जानकारी।

रात में 1 बजे प्राप्त किया गया: 55. 058 संचालक डी. ओ. कक्ष में आया और बताया कि ए. एस. आई. अनूप सिंह संख्या 5331/पी. सी. आर. ने बताया है कि लड़की मॉडल टाउन क्वार्टर के क्वीन मैरी स्कूल के पीछे जल रही थी। उसका नाम मंदीप बेटा स्वर्गीय हरेंद्र सिंह निवासी ए. जे.- 55 सी, शालीमार बाग, आयु 22 वर्ष है। कॉल पर काम करता है

19 (2011) 10 एस. सी. सी. 173 (2-न्यायाधीश पीठ) 20 ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 22 (3-न्यायाधीश पीठ)

905

अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [संजय करोल, जे.] 906

केंद्र। उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त अभिषेक शर्मा ने ऐसा किया है। एलएनजेपी, बुराड़ी पहुँचने पर रोजनामाचा में एक पीसीआर कॉल की जानकारी दर्ज की गई और रिपोर्ट की एक प्रति सी. टी. रामेश्वर, 5053/डीएचजी के माध्यम से एस. आई. बलवंत सिंह को भेजी गई।

एसडी/-

एचसी/डीओ

//सही अनुवादित प्रतिलिपि// "

14. उपरोक्त मृत्यु घोषणा के अवलोकन से पता चलता है कि यह तीसरे व्यक्ति में दर्ज किया गया है, अर्थात्, एसआई अनूप सिंह ने पीड़ित को जलाए जाने की घटना के बारे में बताया था और उसने उसे बताया था कि उसके दोस्त अभिषेक शर्मा ने ऐसा किया था। निस्संदेह, धारा 32 आई. ई. ए. सुनी-सुनाई बातों के नियम के लिए एक अपवाद है, हालाँकि, यह वर्तमान मामले में लागू नहीं होगी।

15. अदालत के समक्ष बयान यह है कि संचालक 'डीओ रूम' में आया और बताया कि एएसआई अनूप सिंह (पीडब्लू 16) ने एक लड़की को जलते हुए पाया था, और उसने उसे बताया कि दोषी-अपीलकर्ता अभिषेक शर्मा ने उसके साथ ऐसा किया था। इसलिए, जैसा कि स्पष्ट है, यह कथन मृतक से तीन डिग्री हटा दिया गया है और इस प्रकार इस अपवाद द्वारा असुरक्षित है क्योंकि कथन के मूल निर्माता से हटाए गए बयानों को अधिक छूट नहीं दी जा सकती है, इसलिए जब समान परिणामों पर निर्भर रहने पर दंडात्मक परिणाम होता है। यदि मृतक का बयान, जैसा कि पीडब्लू 16 को बताया गया है, अदालत के समक्ष वैसा ही होता, तो इसे इस धारा के अर्थ के भीतर एक अंतिम घोषणा माना जा सकता था।

16. डीडी-II, वास्तव में, डॉ. राज (पीडब्लू 8) द्वारा 2 पर किए गए मेडिको-लीगल इन्क्वायरी रजिस्टर में एक प्रविष्टि है: 15 एएम डीटी। 21.09.2007, जो दर्ज करता है "क्वीन मैरी स्कूल, नॉर्थ कैंपस, मॉडल टाउन, दिल्ली के सामने लगभग 1 बजे कथित रूप से जलने की घटना: 40 ए. एम. दिनांकित 21/09/07 जैसा कि रोगी द्वारा बताया गया है "तो इस रिकॉर्ड में काफी अंतर मौजूद है और इसके नीचे अभिषेक द्वारा दर्ज किया गया है"।"

17. यह सच है कि मृत्यु घोषणा को संक्षिप्तता के कारण खारिज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इसमें मृतक की स्थिति का निकटवर्ती कारण और उसका कारण होना चाहिए। यहाँ, यह जलने की चोटों की उपस्थिति बताता है और कहता है कि वही अभिषेक के कारण हुआ था, जो,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

यकीनन, असहनीय है। दोषी-अपीलार्थी की कोई विशेष पहचान नहीं है, और न ही उन साधनों का उल्लेख है जिनके माध्यम से चोटें (पेट्रोल) लगी थीं।

18. डीडी-III को 3 बजे बनाया गया था: 30 एएम से पीडब्लू-17, और इसे नीचे निकाला गया है:

“सरदार हरिंदर सिंह निवासी ए. जे.-55 सी, शालीमार बाग, दिल्ली की 22 वर्षीय मनदीप कौर का बयान, मोबाइल नंबर 9811448556।

मैं उपरोक्त पते पर अपने भाई इंदरजीत सिंह के साथ रह रहा हूँ और सरस्वती विहार में उक्त दूरसंचार के कॉल सेंटर में आधिकारिक सीई मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। आज मैं सुबह 1 बजे अपनी ड्यूटी से मुक्त हुआ, मैं मॉडल टाउन में रहने वाले अपने दोस्त अभिषेक शर्मा के साथ ड्यूटी से वापस आ रहा था। अभिषेक शर्मा मुझे कई दिनों से जान से मारने की धमकी दे रहा था और आज वह मुझे शालीमार बाग में मेरे आवास पर छोड़ने के बावजूद जबरदस्ती क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन III ले गया और क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन III में कार रोकने के बाद, वह अपनी कार से नीचे उतरा और मुझे कार से नीचे उतारा और मुझ पर तेल की बोतल डाली जो उसने अपनी कार में रखी थी और मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और तुम केवल कंपनी के मालिक से

प्यार करते हो। इस समय हम गरमागरम बहस में पड़ गए और हमारे बीच झगड़ा हो गया और अभिषेक ने मुझे माचिस की छड़ी से भरे हुए तेल पर रख दिया। कमीज और सलवार के जलने से मैं अपने शरीर के पिछले हिस्से से घायल हो गया और इस बीच पीसीआर वैन घटनास्थल पर आई और अभिषेक घटनास्थल से फरार हो गया और पीसीआर वैन ने मुझे जेपीएन अस्पताल में भर्ती कराया। अभिषेक ने तेल डालने के बाद मुझे मारने की कोशिश की है। अभिषेक शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कथन सही सुना गया। एस. डी./अंग्रेजी मंदीप कौर ने बलवंत सिंह एस. आई. पी. एस. मॉडल टाउन दिल्ली 21.09.07 ड्यूटी ऑफिशर पी. एस. मॉडल दिल्ली को प्रमाणित किया कि आज डी. डी. No.8A प्राप्त करने के बाद, मैं सी. टी. के साथ जे. पी. एन. अस्पताल गई। परमजीत सिंह नंबर 2678/एन. डब्ल्यू. ने मरीज मंदीप कौर को एम. एल. सी. नंबर 105892 के माध्यम से बयान देने के लिए कहा और कुमारी मंदीप कौर ने अपना बयान दिया, उनका बयान मैंने उनके सामने पढ़ा। उन्होंने अपना बयान सही पाया और अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए। मैंने इसे सत्यापित किया, बयान, शर्तों और एमएलसी से आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध की घटना सामने आई है। इस प्रकार, रक्का को सी. टी. परमजीत 907 के साथ भेजा जाता है।

अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [संजय करोल, जे.] 908 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

नं. 2673/एन. डब्ल्यू. एफ. आई. आर. दर्ज करने और आई. ओ. को एफ. आई. आर. नं. और अपराध दल के साथ सूचित करने के लिए घटना स्थल पर निर्देशित किया जाए। घटना की तारीख और समय दिनांक पूर्वाह्न 1.41 बजे, क्वीन मैरी स्कूल, मॉडल टाउन, दिल्ली के सामने घटना का स्थान, रक्का की तिथि और प्रस्थान: 2.50 ए. एम. दिनांक 21.09.07 एस. आई. बलवंत सिंह डी-800 पी. एस. मॉडल टाउन दिल्ली पी. आई. एस. संख्या 29680224। एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद एफ. आई. आर. की प्रति के साथ मूल रक्का एस. आई. को भेजा गया जो घटना स्थल पर जांच में व्यस्त थे। एफ. आई. आर. की जानकारी डाक द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी।”

19. यह तीसरा बयान दिए जाने के बावजूद, डॉक्टर या मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जो विवेक के नियम के रूप में अभियोजन पक्ष को समर्थन देता है। यह रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिस समय तीसरा बयान दर्ज किया गया था, उस समय मृतक को उसकी चोटों का इलाज कराया गया था। हालांकि, यह सामने नहीं आया है कि उपचार की प्रकृति और उसे किस तरह की दवाएं दी गई थीं। उसके इलाज के लिए जिम्मेदार चिकित्सा दल द्वारा एक सकारात्मक बयान के अभाव में, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि दी गई दवाओं का मृतक की मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का कोई प्रभाव नहीं था। इस संबंध में कोई चिकित्सीय राय रिकॉर्ड में नहीं रखी गई है। इसलिए, डीडी-III के बारे में संदेह के बादल के साथ, यह स्वाभाविक है कि अदालत अन्य परिस्थितियों और साक्ष्यों को सत्य और स्वैच्छिक होने के रूप में दिए गए बयान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देखती है। अन्य वर्तमान परिस्थितियों पर बाद में चर्चा की जाएगी।

20. डीडी-IV की विश्वसनीयता पर इस आधार पर हमला किया गया है कि यह वास्तव में मृतक का मां को दिया गया बयान है और मृतक एक इच्छुक गवाह होगा। पुलिस को दिए गए मां के बयान को नीचे दोहराया गया है:

“ एस. एम. टी. जैस्मेर कौर के कथन की सही अनुवादित प्रति

एफ. आई. आर./डी. डी. नं. 615/07 दिनांक: 21.09.2007 यू/एस 307,302 भारतीय दंड संहिता, पुलिस स्टेशन: मॉडल टाउन, दिल्ली।

जसमेर कौर का पति स्वर्गीय सरदार परविंदर सिंह का वक्तव्य, आयु 61 वर्ष, आवास संख्या 17-एफ, वार्ड No.15, गोविंद नगर, रोपेड, पंजाब

कथन

बयान दिया कि मैं अपने परिवार के साथ उपरोक्त पते पर रहता हूं और मैं गृहिणी हूं। अभिषेक शर्मा, जिसे पुलिस ने एल. एन. जे. पी. अस्पताल में भर्ती कराया था, ने <आई. डी. 1] पर मेरी बेटी पर पेट्रोल छिड़क दिया, उसी दिन मैंने परिवार के सदस्यों के साथ उसे महाराजा अगरसेन अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था की ताकि उसका अच्छा इलाज हो सके। इलाज के दौरान, मेरी बेटी का नाम किमी है। मंदीप कौर का आज अस्पताल में निधन हो गया क्योंकि महाराजा अगरसेन अस्पताल में सुबह लगभग 3.35 बजे, मैंने बीजेआरएम अस्पताल में उनके शव की पहचान की। यह मेरी बेटी की मृत देह है जिसका नाम किमी है। मंदीप कौर, जिनकी फिल्म के सेट पर ही मौत हो गई थी।

बयान को सुना और सही पाया। एसडी/-

जैसमेर कौर

द्वारा प्रमाणित

एसडी/-

एसआई,

बलवंत सिंह पुलिस स्टेशन: मॉडल टाउन, दिल्ली दिनांक: 03.10.2007

एसडी/-

एस. आई., बलवंत सिंह पुलिस स्टेशन: मॉडल टाउन, दिल्ली दिनांक: 03.10.2007” 21. हम देखते हैं कि अपनी जिरह में, यह गवाह 3 अक्टूबर 2007 को पुलिस को कोई बयान देने से इनकार करता है। चाहे जो भी हो, यह मानते हुए कि उसने वास्तव में ऐसा बयान दिया था, हमारा विचार है कि फिर भी, इस तरह के बयान को किसी भी तरह से आरोपी के प्रति अपमानजनक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें उल्लिखित व्यक्ति, यानी अभिषेक शर्मा के संबंध में विवरणों का अभाव है और इसका कोई संबंध नहीं है जो आरोपी व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है।

अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [संजय करोल, जे.] 910

22. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मृत्यु घोषणा किसी भी लिखित या अन्य सत्यापन योग्य रूप में मौजूद नहीं है। यहाँ, केवल हम पीडब्लू-5 (मृतक की माँ) पद के परीक्षा-प्रमुख का उल्लेख कर सकते हैं, जो बयान और गवाही दोनों को एक साथ लेते हुए, डीडी-IV के साक्ष्य मूल्य की जांच की जाएगी।

23. अभियुक्त को कथित रूप से फंसाने वाली उसकी गवाही (मुख्य परीक्षा) का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार निकाला गया है:-

“मंदीप ने मुझे बताया था कि अभिषेक उसे अपने कार्यालय से कार में ले गया था। वह उसे उसके घर पर नहीं छोड़ता था, बल्कि उसे मॉडल टाउन में एक जगह ले जाता था। उसे गाड़ी से बाहर निकाला गया। चूंकि वह बाहर नहीं आई, इसलिए अभिषेक ने उसकी पिटाई की। जैसे ही वह कार से बाहर आई, अभिषेक ने उस पर पेट्रोल डाला और उसे कपड़े पहना दिए। 24. इच्छुक गवाहों पर कानून की सराहना करना महत्वपूर्ण है क्योंकि

इस अदालत द्वारा स्पष्ट किया गया। हरि ओबुला रेड्डी और अन्य बनाम राज्य

आंध्र प्रदेश 21, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि इच्छुक गवाहों का साक्ष्य आवश्यक रूप से अविश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। यहाँ तक कि पक्षपात अपने आप में शपथ की गवाही को बदनाम करने या अस्वीकार करने के लिए एक वैध आधार नहीं है। यह एक अपरिवर्तनीय नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि इच्छुक साक्ष्य केवल तभी दोषसिद्धि का आधार बन सकते हैं जब स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा भौतिक विवरणों में एक भौतिक सीमा तक पुष्टि की जाए। बस इतना आवश्यक है कि इच्छुक गवाहों के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और सावधानी के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि इस तरह की जांच पर, इच्छुक गवाही आंतरिक रूप से विश्वसनीय या स्वाभाविक रूप से संभावित पाई जाती है। उस मामले में, यह अपने आप में, विशेष मामले की परिस्थितियों में, उस पर दोषसिद्धि के आधार पर पर्याप्त हो सकता है।

25. इसके अलावा, पुलिचेरला नागराजू उर्फ नागराजा रेड्डी बनाम।

आंध्र प्रदेश राज्य 22, इच्छुक गवाहों, जो रिश्तेदार हैं, के दायित्व पर विचार करते हुए, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक गवाह के साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वह या तो पक्षपातपूर्ण या इच्छुक है या मृतक का करीबी रिश्तेदार है, अगर यह अन्यथा भरोसेमंद और विश्वसनीय पाया जाता है। उक्त साक्ष्य

21 (1981) 3 एस. सी. सी. 675 (3-न्यायाधीश पीठ) 22 (2006) 11 एस. सी. सी. 444 (2-न्यायाधीश पीठ)

केवल अधिक सावधानी और सावधानी के साथ जांच की आवश्यकता होती है ताकि न तो दोषी बच सके और न ही निर्दोष को गलत तरीके से दोषी ठहराया जाए। यदि, इस तरह की सावधानीपूर्वक जांच पर, साक्ष्य विश्वसनीय और संभावित पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। यदि यह असंभव या संदिग्ध पाया जाता है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। जहाँ गवाह का उद्देश्य दोषी-अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाना है, वहाँ उसकी गवाही को स्वीकार करने से पहले भौतिक विवरणों के बारे में पुष्टि होनी चाहिए।

26. डीडी-IV माँ का बयान है (जो दिल्ली की निवासी नहीं है और ऐसी घटना की सूचना मिलने पर ही दिल्ली पहुंची होगी) जिसमें मृतक ने अपनी माँ को घटना के बारे में विशिष्ट तथ्यों का खुलासा किया था। घोषणा करते समय, ए) स्थिति में और गिरावट और बी) किसी तीसरे पक्ष की अनुपलब्धता का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है, जैसे कि एक डॉक्टर जिसके सामने ऐसा बयान दर्ज किया जा सकता है। दोषी-अपीलार्थी ने बयान की सच्चाई पर इस आधार पर हमला किया है कि मृतक की माँ होने के नाते, पीडब्लू5 एक इच्छुक गवाह है। एक इच्छुक गवाह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना के लिए सामान्य नियम यह है कि इसकी पुष्टि अन्य स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा की जानी चाहिए। मृतक द्वारा माँ को दिए गए बयान की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्र पुष्टि एक अलग पंथ है। ऊपर बताए गए दो कारकों और स्वतंत्र पुष्टि की कमी को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से जब बयान देने वाला व्यक्ति मृतक की माँ है, तो अदालत इस तरह के बयान पर भरोसा करने के लिए नुकसान की भावना और संभवतः क्रोध द्वारा निभाई गई भूमिका को सकारात्मक स्तर तक खारिज नहीं कर सकती है। यदि अन्य व्यक्तियों के मौजूद होने के साथ किसी प्रकार की पुष्टि होती, तो उसी पर भरोसा किया जा सकता था। हालाँकि, इसकी अनुपस्थिति में, उसी पर निर्भरता दोषी-अपीलार्थी के लिए प्रतिकूल होगी, और इसलिए, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

27. इस कथन की इस तरह की अविश्वसनीयता इस तथ्य से बढ़ जाती है कि डीडी-IV के रूप में माने जाने वाले माँ के बयान और उसके बयान के बीच एक भौतिक अंतर है जिसमें वह दावा करती है कि दोषी-अपीलकर्ता ने मृतक को दोषी ठहराने से पहले शारीरिक रूप से हमला किया था। इसके विपरीत, पुलिस अधिकारियों या डॉक्टर को दिए गए अन्य बयानों में से कोई भी ऐसी घटना को नहीं दर्शाता है। इसके अलावा, एमएलसी ने 30 प्रतिशत जलने के अलावा कोई शारीरिक चोट दर्ज नहीं की है। इसे एक सुधार/अतिशयोक्ति कहा जा सकता है जो दोषी को देखने की इच्छा में उत्पन्न होती है-911

अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [संजय करोल, जे.] 912

अपीलार्थी को कथित रूप से किए गए अपराध के लिए दंडित किया गया है। बयान और गवाही के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पुलिस को दिए गए बयान में, यह तथ्य कि "अभिषेक ने उस पर पेट्रोल डाला और उसे गोली मार दी" वहाँ से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।

28. डीडी-आई केवल सवाल उठाता है और घटना का कोई संदर्भ या जवाब नहीं देता है। यह एक ऐसा बयान है जिसमें केवल यह उल्लेख किया गया है कि एक व्यक्ति, यानी दोषी-अपीलार्थी, मृतक की घायल स्थिति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था। इसे ध्यान में रखते हुए और फिर अस्पताल के साथ-साथ जांच अधिकारियों के बाद के आचरण पर ध्यान देना हमें कुछ सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है -क) यह देखते हुए कि घोषणा में केवल अभिषेक शर्मा के नाम का उल्लेख किया गया है और कोई अन्य विवरण नहीं है जो पहचान की प्रक्रिया में प्रासंगिक और सहायक हो सकता है जैसे कि टेलीफोन, पता विवरण, दोषी-अपीलार्थी का विवरण, कार्य स्थान, आदि, यह कैसे है कि जांच अधिकारी नियोक्ता के संपर्क में आए?ख) यदि ऐसा कॉल किया गया था, तो इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है?ग) कथन 1 पर दर्ज किया गया था: 55 सुबह, और कॉल सेंटर के प्रबंधक, जहाँ दोषी-अपीलार्थी और मृतक दोनों कर्मचारी थे, से 2 बजे संपर्क किया गया: 00 ए. एम. जैसा कि उनकी अनियंत्रित गवाही से स्पष्ट है-उपरोक्त को देखते हुए, यह कैसे संभव था?रिकॉर्ड में यह नहीं बताया गया है कि पुलिस ने उस पर कैसे शिकंजा कसा।

29. एक और सवाल जो पूछा जा सकता है वह यह है कि जब डीडी-I की सूचना दी गई थी, और एक डॉक्टर ने डीडी-II लिया था, तो डीडी-III की रिकॉर्डिंग के बाद ही प्राथमिकी क्यों दर्ज की गई थी?हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि डीडी-II के अनुसार, मृतक को पीठ, हाथ, कंधे और बालों में जलन हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप सुपरफाई सियाल और 30 प्रतिशत गहरी जलन हुई थी। ऐसी स्थिति में, क्या यह कहा जा सकता है कि मृत्यु की एक उचित आशंका थी, जिससे बयानों को मृत्यु घोषणा के रूप में स्वीकार किया जा सके?

30. दोषी-अपीलार्थी को अपराध स्थल पर नहीं देखा गया था, और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित करने के लिए अंतिम बार देखे गए सिद्धांत का उपयोग किया गया है कि मृतक और वह घटना के समय और स्थान पर एक साथ थे। डीडी-आई के समय से पुलिस की जांच में क्या हुआ, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है, जब कथित तौर पर, पुलिस को दोषी-अपीलकर्ता के मृतक के खिलाफ यह अपराध करने के बारे में पता चला और जब उसे रात 8 बजे गिरफ्तार किया गया।

31. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि डी. डी.-I और डी. डी.-IV को कुछ हद तक सुनी-सुनाई बातों के आधार पर पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

बिना किसी पुष्टि के एक इच्छुक गवाह। डी. डी.-II के संबंध में, दोषी-अपीलार्थी के प्रथम नाम के अंतर्वेशन और बाद में सम्मिलन के संदेह को पर्याप्त रूप से दूर नहीं किया गया है, क्योंकि प्रमुख अंतर के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। डीडी-III के संबंध में, यह पाया गया है कि जिस मानसिक स्थिति में यह बनाया गया है, उसका पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि

मृतक को दिए गए उपचार पर कोई चर्चा नहीं की गई है। इस तरह के स्पष्टीकरण के अभाव में, इस तरह के बयान पर बिना पुष्टि के भरोसा नहीं किया जा सकता है।

32. इसके अलावा, अभिलेख के अवलोकन पर, हम पूरी तरह से विसंगतियों को देखते हैं। उदाहरण के लिए, पीडब्लू 13 का कहना है कि वह पीडब्लू 17 के साथ लगभग 1 बजे पुलिस स्टेशन से निकला था: 55 में उस अस्पताल में जाने के लिए आया हूँ जहाँ मृतक को भर्ती कराया गया था। वहाँ पहुँचने पर, यह पीडब्लू 13 का मामला है कि मृतक का भाई वहाँ मौजूद था। हालांकि, इसके विपरीत, पीडब्लू 17 का कहना है कि जब वह अस्पताल में थे, "आपातकालीन स्थिति में घायल का कोई रिश्तेदार नहीं आया था।" यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकारियों ने भाई के संपर्क विवरण कैसे और कब प्राप्त किए और उसे अस्पताल लाया। पीडब्लू 5 के बयान से और भ्रम पैदा होता है, जिसने कहा कि वह दिल्ली में नहीं रहती थी और अपने बेटे के साथ यहां आई थी और अगले दिन, यानी 22 सितंबर 2007 को अस्पताल गई थी। दिलचस्प बात यह है कि अभियोजन पक्ष ने भाई से पूछताछ नहीं की, जो अन्य आवश्यक तथ्यों के साथ-साथ दोषी-अपीलार्थी के साथ मृतक के संबंधों पर प्रकाश डाल सकता था।

33. यह निर्विवाद है कि मृतक अपनी मृत्यु से छह दिन पहले तक बोलने की स्थिति में थी जब उसे जीवन समर्थन पर रखा गया था। फिर भी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मृतक के बयान की गैर-रिकॉर्डिंग या डॉक्टरों द्वारा बयान देने के लिए उसकी योग्यता का वास्तविक निर्धारण अस्पष्ट है।

34. इसके अतिरिक्त, हम ध्यान दे सकते हैं कि मृतक की कथित मृत्यु घोषणाओं के अलावा, दोषी-अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि एक मृत्यु घोषणा, यदि यह शिक्षण, उकसाने आदि से मुक्त है, तो दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है। हालांकि, अभिलेख को बारीकी से देखने के बाद, हमारे पास ऐसे साक्ष्य भी नहीं हैं जिनके द्वारा हम नीचे दी गई अदालतों के निर्णयों को बरकरार रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अभिलेख पर कुछ भी इंगित नहीं करता है-दोषी-अपीलार्थी द्वारा वाहन का स्वामित्व; कोई असहमति 913

अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र [संजय करोल, जे.]

या दोषी-अपीलार्थी और मृतक के बीच दुश्मनी, जो इतनी चरम प्रकृति की है कि उसे दोषी-अपीलार्थी पर आरोपित करती है; दोषी-अपीलार्थी और पीड़ित को मारने के लिए उपयोग किए जाने वाले आपत्तिजनक पदार्थ के बीच कोई संबंध जैसे कि किसी व्यक्ति की खरीद या बयान का रिकॉर्ड जो ऐसा पदार्थ दिखाने के लिए है जो दोषी-अपीलार्थी के कब्जे में है, आदि। ये कारक और यह तथ्य कि विचाराधीन अपराध एक खुले सार्वजनिक प्रवेश स्थान पर हुआ, अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करते हैं।

35. उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, दोषी-अपीलार्थी पर मृत्युपूर्व घोषणाओं के आधार पर अपराध का आरोप लगाना, जब उसके नाम के अलावा कोई अन्य भौतिक विवरण नहीं निकाला जा सकता है, अन्यायपूर्ण होगा। इसके अलावा, अन्य परिस्थितियों पर विचार करते समय जो दोषी-

अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा कर सकती हैं या नहीं भी कर सकती हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हम अभियोजन मामले में अस्पष्ट अंतराल बनाते हैं, जो मामले को उचित संदेह से परे की सीमा से कम रखने के लिए पर्याप्त संदेह पैदा करते हैं।³⁶ नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है। दोषी-अपीलार्थी को दिनांकित 21.10.2013 आदेश के माध्यम से दी गई जमानत को स्वीकार कर लिया गया है, और जमानत बांड को खारिज कर दिया गया है।

37. वार्ताकार आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान